Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XV, Issue No. 3, May-2018, ISSN 2230-7540

भारतीय शिक्षा प्रणाली पर टेक्नोलॉजी का प्रभाव

Vasundhara*

Ph.D. Shodh Chhatra, Maharaj Vinayak Global University, Jaipur

***सारांश** - किसी भी राष्ट्र अथवा समाज में शिक्षा सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तित्व निर्माण तथा सामाजिक व आर्थिक प्रगति का मापदंड होती है। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश प्रतिरूप पर आधारित है जिसे सन् 1835 ई॰ में लागू किया गया।*

जिस तीव्र गति से भारत के सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक परिदृश्य में बदलाव आ रहा है उसे देखते हुए यह आवश्यक है कि हम देश की शिक्षा प्रणाली की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, चुनौतियों तथा संकट पर गहन अवलोकन करें।

सन् 1835 ई॰ में जब वर्तमान शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी तब लार्ड मैकाले ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य भारत में प्रशासन के लिए बिचौलियों की भूमिका निभाने तथा सरकारी कार्य के लिए भारत के विशिष्ट लोगों को तैयार करना है।

इसके फलस्वरूप एक सदी तक अंग्रेजी शिक्षा के प्रयोग में लाने के बाद भी 1935 ई॰ में भारत की साक्षरता दस प्रतिशत के आँकड़े को भी पार नहीं कर पाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता मात्र 13 प्रतिशत ही थी।

इस शिक्षा प्रणाली ने उच्च वर्गों को भारत के शेष समाज में पृथक् रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश समाज में बीसवीं सदी तक यह मानना था कि श्रमिक वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने का तात्पर्य है उन्हें जीवन में अपने कार्य के लिए अयोग्य बना देना। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने निर्धन परिवारों के बच्चों के लिए भी इसी नीति का अनुपालन किया।

***मुख्य शब्द** – शिक्षा, प्रणाली, आधुनिक*

----------X----------

भूमिका

लगभग पिछले दो सौ वर्षों की भारतीय शिक्षा प्रणाली के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह शिक्षा नगर तथा उच्च वर्ग केंद्रित, श्रम तथा बौद्धिक कार्यों से रहित थी। इसकी बुराइयों को सर्वप्रथम गाँधी जी ने 1917 ई॰ में गुजरात एजुकेशन सोसायटी के सम्मेलन में उजागर किया तथा शिक्षा में मातृभाषा के स्थान और हिंदी के पक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर तार्किक ढंग से रखा। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में शांति निकेतन, काशी विद्यापीठ आदि विद्यालयों में शिक्षा के प्रयोग को प्राथमिकता दी गई।

शिक्षा के महत्व को समझते हुए भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए शिक्षण संस्थाओं व विभिन्न सरकारी अनुष्ठानों आदि में आरक्षण की व्यवस्था की। पिछड़ी जातियों को भी इन सुविधाओं के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया। स्वतंत्रता के बाद हमारी साक्षरता दर तथा शिक्षा संस्थाओं की संख्या में नि:संदेह वृद्धि हुई है परंतु अब भी 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या निरक्षर है।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के नए चेहरे, निजीकरण तथा उदारीकरण की विचारधारा से शिक्षा को भी 'उत्पाद' की दृष्टि से देखा जाने लगा है जिसे बाजार में खरीदा-बेचा जाता है। इसके अतिरिक्त उदारीकरण के नाम पर राज्य भी अपने दायित्वों से विमुख हो रहे हैं।

इस प्रकार सामाजिक संरचना से वर्तमान शिक्षा प्रणाली के संबंधों, पाठ्यक्रमों का गहन विश्लेषण तथा इसकी मूलभूत दुर्बलताओं का गंभीर रूप से विश्लेषण की चेष्टा न होने के

www.ignited.in

कारण भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली आज भी संकटों के चक्रव्यूह में घिरी हुई है। प्रत्येक दस वर्षों में पाठ्य-पुस्तकें बदल दी जाती हैं लेकिन शिक्षा का मूलभूत स्वरूप परिवर्तित कर इसे रोजगारोन्मुखी बनाने की आवश्यकता है।

हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली गैर-तकनीकी छात्र-छात्राओं की एक ऐसी फौज तैयार कर रही है जो अंततोगत्वा अपने परिवार व समाज पर बोझ बन कर रह जाती है । अत: शिक्षा को राष्ट्र निर्माण व चरित्र निर्माण से जोड़ने की नितांत आवश्यकता है।

शिक्षा का सही उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करके उनको देश का आदर्श नागरिक बनाना है । वे तभी ऐसा कर सकेंगे जब शिक्षा समाज करने के बाद वे अपने पैरों पर खड़े होकर स्वय रोटी-रोजी कमाने लायक बन सके। आज हमारी शिक्षा उन्हें अक्षरज्ञान देकर विविध विषयों का सैद्धांतिक ज्ञान तो देती है, पर उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने योग्य नहीं बना पाती ।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये शिक्षाविदों ने देश के सामने एक नई शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया, जिसे १०+२+३ प्रणाली कहा जाता है । इस व्यवस्था के अन्तर्गत विद्यार्थी को स्नातक बनने में कुल 15 वर्ष का समय लगेगा। पहले दस वर्ष स्कूल में अक्षरज्ञान तथा सामान्य विषयों की पढाई के लिये लगाये जायेंगे ।

इस दौरान सभी मूल विषयों का सामान्य ज्ञान दिया जायेगा, जिनमें भाषायें (अंग्रेजी, हिन्दी, तथा मातृभाषा या एक अन्य भाषा), गणित, मानवीकी सामान्य विज्ञान, सामाजिक ज्ञान जैसे विषय पढाये जायेंगे। इसके बाद एक सार्वजनिक परीक्षा होगी, जिसे माध्यमिक परीक्षा का नाम दिया गया है। यदि विद्यार्थी इसके बाद पढ़ाई छोड़ना चाहेंगे, तो उन्हें क्लर्क आदि जैसी सामान्य नौकरियाँ मिल सकेंगी।

माध्यमिक परीक्षा के बाद दो वर्ष की अतिरिक्त पढ़ाई भी स्कूलों में ही होगी, जिसे उच्चतर माध्यमिक नाम दिया गया है। यह पुराने इंटरमीडियट के समकक्ष होगी । इन दो वर्षो में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जायेगा। इस व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त करके लोग अपना रोजगार करने में समर्थ हो सकेंगे ।

जो व्यक्ति उच्च शिक्षा पाना चाहेंगे, उनके लिए चुने हुए विषयो की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध होगा। उदाहरण के लिए डॉक्टरी, इंजीनियरिंग अथवा ऐसी ही किसी विशेष शिक्षा को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इनसे संबंधित विषयों का विशेष ज्ञान दिया जायेगा तथा अन्य उच्च शिक्षा के विषयों के आगे के अध्ययन का आधार प्रदान किया जायेगा। इन दो वर्षों की पढाई के बाद पुन: सार्वजनिक परीक्षा होगी ।

इस उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय की +3 वर्ष की शिक्षा के लिये केवल कुशाग्र बुद्धि चुने हुये छात्र ही लिये जायेंगे। सामान्य औसत विद्यार्थियों की शिक्षा १०+२ के बाद ही समाप्त हो जायेगी। इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या अन्य विशेष शिक्षा संस्थाओं में १०+२ के बाद प्रवेश मिल सकेगा ।

भारतीय शिक्षा प्रणाली पर टेक्नोलॉजी का प्रभाव

इंटरनेट, मोबाइल फोन, मोबाइल एप्लिकेशन, टैबलेट, लैपटॉप और अन्य आधुनिक उपकरणों के विकास के कारण आज की दुनिया की अधिक से अधिक चीजें डिजिटल हो रही हैं। भारत के महानगरों और अन्य शहरों की शिक्षा प्रणाली भी काफी हद तक आधुनिकीकृत हो गई हैं, जिससे डिजिटलीकरण के लिए रास्ता बन गया है। डिजिटल शिक्षा कई अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों के साथ-साथ भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में अपनी जगह बना रही है और पारंपरिक कक्ष प्रशिक्षण का स्थान ले रही है।

वह दिन गुजर गए हैं, जब कक्षा में प्रशिक्षण पाठ्य पुस्तकों द्वारा कराया जाता था। शिक्षक अपनी बातों को समझाने के लिए ब्लैकबोर्ड का इस्तेमाल करते थे और छात्र उन शब्दों को अपनी कॉपियों पर लिखते थे। सीखने के लिए छात्र अध्यापन और पारंपरिक रूप से कार्य-आधारित तरीकों के लिए शिक्षकों पर आधारित रहते थे और लिखने और याद करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे। हालांकि अब ज्यादातर स्कूलों में चाक का उपयोग न के बराबर हो गया है। आजकल डिजिटल शिक्षण जैसे पीपीटी, वीडियों प्रस्तुतियों, ई-लर्निंग विधियों, अभ्यास संबन्धी डेमो, ऑनलाइन प्रशिक्षण और अन्य डिजिटल पद्धतियों या

www.ignited.in

प्लेटफार्मों के उपयोग के साथ कक्षा में शिक्षण अत्यधिक संवादात्मक हो गया है।

डिजिटल शिक्षा के लाभ

- **संवादात्मक:** डिजिटल शिक्षा के जरिए कक्षाओं का शिक्षण अधिक मजेदार और संवादात्मक बन गया है। बच्चे इस पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। वह न केवल इसे सुन रहे हैं, बल्कि इसे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, जिससे उनके सीखने की क्षमता में काफी इजाफा हो रहा है। ध्वनियों और दृश्यों के माध्यम से बच्चें आसानी से सीख रहे हैं।

- **विवरणों पर ध्यान देना:** संवादात्मक ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण या संवादात्मक स्क्रीन के माध्यम से व्यावहारिक सत्र में शैक्षणिक सामग्री छात्रों को विवरणों पर और अधिक ध्यान देने में मदद करती है, जिससे वे अपनी गतिविधियों को अपने दम से पूरा करने में सक्षम होते हैं।

- **शीध्र समापन:** पेन और पेंसिल की बजाय टैब, लैपटॉप या नोटपैड के उपयोग की सहायता से बच्चे अपने कार्यों को कम समय में पूरा कर लेते हैं।

- **शब्दावली :** सक्रिय ऑनलाइन स्क्रीन की सहायता से छात्र अपनी भाषा कौशल में सुधार कर लेते हैं। ई-बुक से या ऑनलाइन अध्ययन सामग्री के जरिए वे नए शब्द सीखते हैं और अपनी शब्दावली का विस्तार करते हैं।

- **अपनी क्षमता से सीखें:** कई बार, एक छात्र अपने शिक्षक से कक्षा में प्रशिक्षण के दौरान, प्रश्न पूछने से झिझकता है। लेकिन डिजिटल शिक्षा के माध्यम से भले ही वह एक बार में कुछ भी न समझ पाए, फिर भी वह अपनी दुविधा को मिटाने के लिए रिकॉर्डिंग सत्र में शामिल हो सकते हैं। प्रौद्योगिकी एक छात्र को उनकी योग्यता के अनुसार सीखने में मदद करती है।

- **उपयोगकर्ता के अनुकूल:** डिजिटल शिक्षा के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह उपयोगकर्ता के अनुकूल है। आप कहीं भी हों, आप अपने पाठ्यक्रम को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। आप यात्रा के दौरान भी सीख सकते हैं। यहाँ तक कि किसी कारणवश अगर आप कुछ दिन कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाएं हैं, फिर भी आप स्कूल की वेबसाइट से कक्षा की सामग्री और फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।

- **अपने आप सीखें:** इसके अलावा, आजकल ऑनलाइन अध्ययन सामग्री आसानी से उपलब्ध है। यहाँ तक कि अगर पूरी शिक्षा प्रणाली डिजिटल रूप में नहीं है, फिर भी छात्र अपनी क्षमताओं के आधार पर डिजिटल सामग्री का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए छात्र शिक्षक के बिना भी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, विभिन्न विषयों के विशेष ऑनलाइन अध्ययन के अनुखंडो का उपयोग कर सकते हैं।

- **बाह्य मार्गदर्शन:** ऑनलाइन शिक्षा के साथ-साथ छात्र दूर के सलाहकारों और संकाय से मार्गदर्शन प्राप्त करने या प्रश्नों को हल करने के लिए उनकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष

नई शिक्षा प्रणाली को पूर्णरूप से सफल बनाने के लिये अभी बहुत-कुछ करना है । परीक्षा प्रणाली में सुधार अत्यावश्यक है, ताकि बढ़ती हुई नकल करने की प्रवृत्ति रुक सके । शिक्षा के स्तर में सुधार के लिये विद्यालयों के लिये सहायक सामग्री की व्यवस्था तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण की जरूरत है । इसके लिये बहुत बडी धनराशि चाहिये । यदि हम दृढता से इस दिशा में प्रगति करते रहे, तो कुछ वर्षों में हमारा शिक्षा का स्तर विश्व के किसी भी विकसित देश के स्तर से नीचा नहीं रहेगा।

सन्दर्भ

1. टैवंगारियन डी., लेपोल्ड एम., नोल्टिंग के., रोज़र एम., (2004). क्या ई-शिक्षा व्यक्तिगत शिक्षा का सामाधान है? जर्नल ऑफ ई-लर्निंग, 2004.

2. Means, B.; Toyama, Y.; Murphy, R.; Bakia, M.; Jones, K. (2009). Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies (PDF), अभिगमन तिथि 20 अगस्त 2009

3. केर्कमैन, एल. (2004). ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा मिडकरियर छात्रों को आकर्षित करती है। क्रॉनिकल ऑफ़ फिलान्थ्रोपी, 16(6), 11-12। ऐकडमिक सर्च प्रीमियर के डेटाबेस से उद्धृत।

4. TonyBates.ca

5. ईसी (2000). आयोग से पत्रव्यवहार: ई-शिक्षा - कल की शिक्षा "तेजस ऐट नीट" (Tejas at Niit) की डिजाइनिंग। ब्रसेल्स: यूरोपीय आयोग

6. नैगी, ए. (2005). ई-शिक्षा का प्रभाव, पी. ए. ब्रुक, ए. बुछोल्ज़, जेड. कार्सन, ए. ज़ेर्फास (संस्करण) में। ई-सामग्री: यूरोपीय बाज़ार की प्रौद्योगिकियां एवं दृष्टिकोण। बर्लिन: स्प्रिंगर-वर्लैग, pp. 79-96

7. "स्लोन कंसोर्टियम"

8. आई. ई. एलन एवं जे. सीमैन (2008). पाठ्यक्रम का स्थायीत्वकरण: संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑनलाइन शिक्षा, नीडहम एमए: स्लोन कंसोर्टियम

Corresponding Author

Vasundhara*

Ph.D. Shodh Chhatra, Maharaj Vinayak Global University, Jaipur